

220



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वातिघर म०प्र०

निग०प्र०क्र०

16/6/16 निग-2099-I-16

राज. के. शास्त्री  
रा आज दि. 29/6/16  
स्तुत  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वातिघर

हुकुमतनय श्री रामबगल यादव निवासी ग्राम  
पहाड़ी खुर्द तह. वजिला टीकमगढ म.प्र.  
निगरानीकर्ता

बनाम

1. विनोद तनय स्व. श्री मोहन यादव निवासी ग्राम  
सुनोरा खिरिया तह. वजिला टीकमगढ म.प्र.
2. म०प्र० शासन .. प्रतिनिगरानीकर्ता

S. K. Sharma  
Adv.  
28/6/16

निगरानी प्रस्तुत विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला  
टीकमगढ म.प्र. के प्र०क्र० 03/स्व. निग./2014-15 मे पारित आदेश  
दिनांक 24/5/2016 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता/ आवेदक विनोद यादव ने एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय मे दिया था कि ग्राम सुनोरा खिरिया की भूमि ख. न. 187 रकवा 0.405 आरे. पर अबैध रूप से बिना प्रकरण क्र. के दफ्तरी प्रचिह्न को स्वमेव निगरानी मे ली जा कर निरस्त किए जाने वास्तुवा उक्त प्रतिनिगरानीकर्ता का आवेदन प्रथम दृष्टया ही गलत था क्योंकि निगरानीकर्ता को विधिवत तरीके से प्रकरण क्र. 27/अ-1984/वर्ष 2000-01 आदेश दिनांक 12/07/2001 के द्वारा विधिवत तरीके से ग्राम सुनोरा खिरिया की भूमि ख. न. 187 रकवा 0.405 हे. लगान 1.25 पैसे का व्यवस्थापन किया गया था ऐसा व्यवस्थापन कंडिका 24 राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत किया जाता है ऐसे आदेश के विरुद्ध माननीय प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के यहाँ अपील प्रस्तुत की जा सकती थी परंतु प्रतिनिगरानीकार के द्वारा अपील प्रस्तुत न करने का एक बहाना लिखा कि उक्त प्रकरण की नकल नहीं मिल रही है इस कारण यह आवेदन स्व० निगरानी मे लेने का वाक्य दिया जा रहा है निगरानीकार ने अपनी आपत्ति के विरुद्ध विन्द् क्र. 1 मे उक्त विधि विन्द् को लेख किया था परंतु अधीनस्थ -

3

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आपत्ति का निराकरण न करते हुए उक्त आपत्ति पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2099-एक/2016

जिला टीकमगढ़

हुकुम विरूद्ध विनोद व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 03/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019</p>